भाजपा राष्ट्रीय परिषद्
नई दिल्ली, 2–3 मार्च, 2013
आर्थिक संकल्प

मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार संप्रग सरकार की पहचान बन गये हैं। देश को एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आर्थिक मंत्री के कलंक को भी झेलना पड़ रहा है, इनके अधीन प्रत्येक आर्थिक मैक्रोपैरामीटर में निरंतर गिरावट आई है। भाजपा भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से गिरती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। इसके चलते आम आदमी की तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं। भाजपा कांग्रेस संप्रग–नीत सरकार को गैर–कार्य–निष्पादन, नीति पंगुता और दिशाहीनता के लिए दोषी ठहराती है।

<u>आर्थिक स्थिति का कमजोर होना – जहां से चले थे, वही लौट आना</u>

भाजपा नीत राजग सरकार को 1998 में 4% की कम विकास दर विरासत में मिली थी, परन्तु भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बनाने के प्रति अपनी वचनबद्धता के कारण इसने अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप भारत ने कई दशकों में पहली बार वर्ष 2004 में 8.25% विकास दर हासिल की थी। यह उस समय था जब भाजपा नीत राजग् सरकार ने कार्यभार छोड़ा था।

कांग्रेस नीत संप्रग सरकार को आर्थिक विकास और उसके समेकन के लिए एक बहुत बेहतर स्वप्न की आशा भी नहीं थी। उच्च विकास दर और स्वस्थ्य भुगतान संतुलन की स्थिति के साथ–साथ कम मुद्रास्फीति और कम ब्याज दर सुदृढ़ आर्थिक विकास और मैक्रो आर्थिक स्थिरता को हासिल करने के लिए बेहतर आदर्श थे।

तथापि, इस बात से सभी निराश हुए हैं कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने आर्थिक बदलाव का रास्ता अपनाया है। **अपने 9 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 5% मुद्रास्फीति दर के साथ 10% विकास दर प्राप्त करने के बजाए संप्रग सरकार को इसके बिल्कुल विपरीत उपलब्धि हुई – 10% की मुद्रास्फीति दर और 5% की विकास दर। संकीर्ण से संकीर्ण अनुमान के अनुसार भी कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के अधीन आर्थिक कुप्रंधन से देश कई दशक पीछे चला गया है। इसके मुकाबले यह देखने योग्य बात है कि राजग ने 4% सकल घरेलु उत्पाद विकास से शुरूआत की थी और वह देश को 8 प्लस प्रतिशत विकास के पथ पर ले आई, जबकि संप्रग को 8 प्लस प्रतिशत जी.डी.पी. की विकास दर विरासत में मिली थी और यह इसे कम करके 4% विकास दर पर ले आई है।**

<u>मैक्रो स्थिति</u>

इस संबंध में स्थिति और भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि गिरती हुई आर्थिक दर के साथ–साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में गिरावट आ रही है। कुल मिलाकर आई.आई.पी. (IIP) सूचकांक लगातार गिर रहा है और इस समय दिसम्बर 2012 के माह के लिए यह सूचकांक 0.6% था। कोयला, खनन, ऊर्जा, उर्वरक और प्राकृतिक गैस जैसे कोर क्षेत्र नकारात्मक जोन में आते हैं।

लगातार बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा नाजुक स्थिति में पहुंच गया है। इस समय राजकोषीय घाटा 5.5% के आस–पास है। परन्तु इस बात को किसी से भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह और बढ़ सकता है। ऐसा प्रत्येक बजट में राजकोषीय घाटा को कम करने के सरकार द्वारा हर वर्ष दिये गये आश्वासन के बावजूद हो रहा है। **यह नोट करना दिलचस्प बात होगी कि राज्यों का राजकोषीय घाटा कम हो रहा है।** अतः केंद्र सरकार मुख्य रूप से और एक मात्र रूप से बढ़ते राजकोषीय घाटे के लिए उत्तरदायी है और राज्य सरकारों पर इस संबंध में बराबर का दोषी ठहराना इसके लिए उचित नहीं होगा।

भाजपा नीत राजग सरकार ने ऐतिहासिक आर्थिक कानून–राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (FRBM) अधिनियम बनाया था ताकि राजकोषीय घाटे को 3% से नीचे रखा जा सके। दुर्भाग्यवश, कांग्रेस नेतृत्व के अधीन केन्द्र सरकार ने इस संकल्प के प्रति कोई वचनबद्धता नहीं निभाई जबकि राज्य सरकारें FRBM लक्ष्यों क अनुसार मौटे तौर पर कार्य कर रही है जैसा कि उनके वित्तीय आंकड़ों से पता चलता है।

चालू खाता घाटा (CAD) भी गहरी चिंता का विषय है क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद के 5.4% के स्तर पर है जो स्वीकार्य नही है। वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी एक महत्वपूर्ण कारण बचतों और निवेश दरों में भारी कमी जिसके कारण न केवल आर्थिक विकास कम हुआ है बल्कि दुर्भाग्यवश CAD और राजकोषीय घाटे के वर्तमान असंतुलन को भी बढ़ाया है। इससे भी खराब बात यह है कि सरकार अल्पकालीन ऋण और उसके द्वारा उधार लेने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इससे वास्तव में CAD का वित्त पोषण हो रहा है। **यहां तक कि अर्थव्यवस्था का नया–नया छात्र भी जानता है कि ऐसी स्थिति अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों के संसाधनों को समाप्त करने जैसा है।**

लगातार बढ़ते CAD और राजकोषीय घाटे के परिणामस्वरूप गत् 12 महीनों में रूपये की कीमत में 20% से अधिक की गिरावट आई है। इसके मुकाबले अनेक अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है।

भारत का विदेशी ऋण 260 विलियन डालर से बढ़कर 340 बिलियन डालर हो गया है जो 30% बैठता है। **ऐसा पहली बार हुआ कि विदेशी ऋण विदेशी आरक्षित पूंजी से अधिक है।**

संभाव्य अंतर्राष्ट्रीय डॉउन ग्रेड के प्रत्युत्तर में सरकार ने जल्दबाजी में अनेक निर्णय लेने का फैसला किया है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में कीमते बढ़ गई हैं और योजनागत् व्यय को कम कर दिया गया है। भाजपा ऐसे प्रत्यावर्त्ती कदमों की निंदा करती है।

यहां तक कि रूपयों में एफ.डी.आई. भी पिछली तिमाही में घटकर 43% हो गई है जो कि बहुत अधिक है। हम एक विचित्र स्थिति का सामना कर रहे हैं जिससे घरेलू निवेशक भी विदेशों में निवेश के अवसर ढूंढ़ रहे हैं। **वर्ष 2000 में जितना घरेलू निवेश विदेशों में गया वह आंतरिक एफ. डी.आई. का 10% बैठता है। वर्ष 2011–12 में यह घरेलू एफ.डी.आई. का 50% बैठता है।**

स्थिति को सुधारने के लिए वित्तीय रिस्पांस भी पक्षपातपूर्ण है। संप्रग सरकार राजस्व जुटाने में अपेक्षित कुशलतापूर्वक कार्यवाही करने के बजाए करों और कीमतों को बढ़ाने में लगी हुई है जिसके कारण आम आदमी पर बोझ और बढ़ता जा रहा है।

मुद्रास्फीति – वास्तविक दुःखदायी कारण –

संप्रग सरकार की सबसे बड़ी विफलता मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने और उसे कम करने में उसकी असफलता है। दुर्भाग्यवश, मुद्रास्फीति किसी प्राकृतिक विपदा के परिणामस्वरूप नहीं है बल्कि इस सरकार का दिया हुआ उपहार है। अनाज भण्डार के कुप्रंबधन और वितरण में विसंगतियों के कारण ही मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है। जहां देश के गोदामों में मात्र 30 मिलियन टन अनाज का स्टॉक करना चाहिए था वहां संप्रग सरकार ने 70 मिलियन टन अनाज का विशाल भण्डार स्टॉक किया जिसके परिणामस्वरूप बाजार में अनाज की कमी हो गई और उनकी कीमतें बढ़ गई। **दुर्भाग्यवश, मात्रा से अधिक अनाज को भारत के कुपोषित लाखों बच्चों को बांटने के बजाए उसे गोदामों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और उसके बाद उसे विदेशों में पशुओं के चारे के रूप में निर्यात किया गया और शराब बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया।**

संप्रग सरकार ने अभी तक 13 बार ब्याज दरों में वृद्धि करके धन आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति के मांग पक्ष की आरे ही ध्यान दिया है, परंतु आज तक इससे अधिक महत्वपूर्ण आपूर्ति पक्ष के मुद्दों पर ध्यान देने का बिल्कुल ही प्रयास नहीं किया है। खाद्य तेल, जो 2003 में आयात सूची की कोई मद नहीं थी, अब वह दस बिलियन यू एस डॉलर आयात की मदद बन गया है। आज देश की खाद्य तेल की 50 प्रतिशत की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।

आज लोग अभूतपूर्व महंगाई से पिस रहे हैं, वे राहत चाहते हैं। इसके बदले सरकार ईंधन उत्पादों के डिरेग्यूलेशन कर रही है और ऊंची कीमतों, करो, सेवा प्रभारों को और बढ़ाने जा रही है। डीजल के मूल्यों में एक मुश्त 5 रूपये बढ़ा दिए गए और इसके बाद प्रति माह 50 पैसे की किश्त के अनुसार 10 रूपये बढ़ा दिये हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ता की एक नई श्रेणी सृजित की है और एक ही बार में 11 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ा दी है। इस दौरान जमीनी हकीकत की उपेक्षा करते हुए सरकार ने गैस सिलिंडरों की सीमा बांध दी है जिसके परिणामस्वरूप काफी भ्रम पैदा हो गया है और पिछले दरवाजे से कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सभी प्रकार के परिवहन लागत तुरंत बढ़ जाने के साथ–साथ इसका सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वैश्विक अनुभवों से यह पता चलता है कि फारवर्ड एक्सचेंज के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वायदा बाजार से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है फिर भी सरकार ने इस पहलू की अनदेखी की है।

मुद्रास्फीति से कामकाजी और मध्यम वर्ग के लोगों की वास्तविक आय में कमी होती है। जिनके वेतन और मजदूरी को बढ़ते हुए मूल्यों के साथ नहीं जोड़ा जाता। इससे जीवन स्तर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और जीवन यापन कठिन हो जाता है। मुद्रास्फीति भी एक प्रक्रिया है जिसके कारण सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे गरीब वर्गों से गैर गरीब वर्गों को वास्तविक आस्तियों का अंतरण आसान हो जाता है।

भाजपा मांग करती है कि डीजल, गैस, पेट्रोल, रेल और अन्य सेवाओं के लिये सभी प्रशासनिक मूल्यों में की गई वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए क्योंकि आम आदमी अभूतपूर्व आर्थिक बोझ के नीचे दबा हुआ है।

इसकी पीड़ा उस समय देखने को मिली जब 50 मिलियन से अधिक कामगारों और कर्मचारियों ने निरंतर बढ़ रही महंगाई और संप्रग सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों पर असंतोष व्यक्त करने के लिए दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी। सरकार के पास न तो मजदूरी और मूल्य नीति है और न ही उसके पास एक उचित सप्लाई साइड रिजीम है।

लूट जारी है

कांग्रेस नीति यूपीए सरकार भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला और फार्मलोन माफी घोटाला अभी हाल ही में इस सरकार के न खत्म होने वाले भ्रष्टाचार की सूची में जुड़े हैं। यह बात नोट करने के लिए दिलचस्प होगी कि इटली ने जिसे हेलीकाप्टर सौदे से लाभ होना था, भ्रष्टाचार के पता लगने के तुरंत बाद रिश्वत देने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की, जबकि भारत जिसे, इस घोटाले से नुकसान हुआ है, रिश्वत लेने वालों का पता लगाने के लिए तैयार नहीं है। ''द फैमिली'' के रूप में रिश्वत लेनेवालों के उल्लेख के बारे में रहस्य अभी भी बना हुआ है। सरकार ने इस मामले में सीबीआई द्वारा जांच के आदेश दे दिए हैं परंतु वह इसे न्यायालय की निगरानी में कराने के लिए तैयार नहीं है। इसने न तो कोई एफआईआर दर्ज की है न ही कोई एल आर जारी किया है। वह यह जानते हुए जेपीसी गठन की पेशकश कर रही है कि वह जांच करने और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेगी। इससे यह अटकलबाजियां लगाई जाती हैं कि सरकार सच्चाई का पता लगाने और दोषियों को दंडित करने के बजाए रिश्वत लेने वालों को बचाने में ज्यादा रूचि रखती है।

एक बहुत बड़ा फार्म लोन माफी घोटाले का पर्दाफाश कैग ने किया है। 34 लाख से अधिक किसानों को, जो लोन माफी के पात्र थे, योजना के त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाया, इसके बजाए 24 लाख से अधिक पात्र किसानों को योजना के धीमे क्रियान्वयन के कारण भारी लाभ मिल गया। **भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक है। ईमानदारी से निवेश को हतोत्साहित करने का कारक है। और यह बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे का भी कारण है। सरकार ने अपने घोटालों पर पर्दा डालने के उद्देश्य से जानबूझकर कैग की आलोचना की है और लोकलेखा समिति की कार्रवाई में बाधा डाली है। भाजपा मांग करती है कि इन दोनों घोटालों की जांच न्यायालय की निगरानी में कराई जानी चाहिए और वह यह भी मांग करती है कि पात्र किसानों का तुरंत लाभ दिया जाना चाहिए।**

प्रशासन की कमी

संप्रग सरकार अपनी अंदरूनी विफलताओं के लिए बहाने ढूंढ़ने और लगातार बाहरी कारकों को दोष देने में माहिर है। इसके द्वारा नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन करना, अनिर्णय और कुप्रशासन वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने विशाल प्रा.तिक संसाधनों को निःशुल्क अथवा वास्तविक लागत की मामूली दर पर बांटे जिसके कारण पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका। कोयला और स्पेक्ट्रम ऐसे कुछ उदाहरण हैं। कोयले के वितरण को सस्ती बिजली की निश्चित सप्लाई से नहीं जोड़ा गया इसके कारण इन्हें भारी भ्रष्टाचार का उदाहरण माना जाता है।

अर्थ–व्यवस्था के सभी वर्गों में अनिर्णय की स्थिति पूरी तरह से विद्यमान है। प्रधानमंत्री ने विद्युत संयंत्रों को कोयले की त्रुटिपुर्ण सप्लाई पर निगरानी रखने के लिए एक समिति बनाई थी जो अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई है। उन्होंने तेजी से स्वीकृति दिए जाने के लिए एक राष्ट्रीय निवेश बोर्ड बनाने का भी प्रयास किया था जिसे कांग्रेस पार्टी में उनके राजनीतिक आकाओं ने समाप्त कर दिया। आखिरकार, उन्होंने निवेश के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया, जिसने गत चार वर्षों में बहुत ही कम परियोजनाओं को स्वी.ति प्रदान की है। प्रधानमंत्री की दो विशिष्ट फ्रेट कोरिडोर बनाने की सुनहरी परियोजना पूरी तरह से अधर में लटकी हुई है और यहां तक कि अधूरी परियोजनाओं को पूरा

करने का उनका प्रस्ताव अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आया है। यहां तक कि अनेक परियोजनाओं के लिये विद्युत खरीद समझौते भी नहीं हो पायें हैं। प्रधानमंत्री की पूर्ण अकुशलता उस समय देखने को मिली, जब उन्होंने देश को बताया कि ''पैसा पेड़ो पर नहीं उगता''।

यह आर्थिक अव्यवस्था के अलावा और कुछ नहीं है जिसका कारण सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्दर अन्दरूनी कलह एवं भ्रम है। यह बात एक ओर योजना आयोग द्वारा और दूसरी ओर एन.ए.सी. द्वारा व्यक्त किये बिल्कुल विरोधी विचारों से साबित होती है। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग–अलग विचार व्यक्त करने से इस स्थिति की पुष्टि होती है। इसका आभास गत् वर्ष के बजट में भी मिलता है। जब पूर्व–प्रभावी करों एवं जी.ए.ए.आर. (GAAR) की घोषणा की गई थी और बाद में इन्हें वापस ले लिया गया और उन्हें स्थगित कर दिया गया था।

<u>भाजपा नीत राजग बनाम संप्रम</u>

बुनियादी विकास पर राजग को विशेष प्रयास को गत् एक दशक में संप्रग को दूर दृष्टिविहीन प्रशासन के कारण धक्का लगा। राजग शासन काल में राजपथों का निर्माण प्रतिदिन 11 कि.मी. के स्तर पर पहुँच गया था। आज प्रतिदिन 22 कि.मी. राजपथ बनाने के बड़े–बड़े वायदे के बावजूद यह मात्र तीन कि.मी. प्रतिदिन रह गया है जो बहुत ही निराशाजनक बात है। ईस्ट–वेस्ट और नार्थ–साऊथ को कोरिडोर अभी तक दिवास्वप्न बने हुऐ हैं। यहां तक की ग्राम सड़क योजना भी धीमी पड़ गई है।

विद्युत उत्पादन, जिसका लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में 78000 मेगावाट रखा गया था, वास्तव में केवल 54000 MW हो पाया है। रेल बंदरगाहो, तेल और गैस जैसे अन्य बुनियादी क्षेत्रों का कार्य–निष्पादन पूरी तरह से निराशाजनक है। राजगने चार वर्षो के दौरान 40 मिलियन अतिरिक्त परिवारों को गैस कनैक्शन देना सुनिश्चित किया था जबकि संप्रग सरकार गत् 9वर्ष के कार्यकाल में इन आंकड़ो के बराबर भी नहीं पहुंची हैं। एम.टी.एन. एल., बी.एस.एन.एल, एन.टी.पी.सी., एयर इण्डिया जैसे सरकारी क्षेत्र के उपकरण उनके राजनीतिक आंकड़ो द्वारा दुरूप्रयोग और कुप्रबंधन के कारण हुई भारी हानि की वजह से बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप सकल निवेश में भी गिरावट आई है।

संप्रग ने अभी तक देश को 'जॉबलेस ग्रोथ' ही दी है। जहां भाजपा नीत एनडीए ने अपने शासनकाल के दौरान 8 मिलियन नौकरियों का सृजन किया था, वहां संप्रग ने केवल 2 मिलियन नौकरियों का सृजन किया है। सरकार की मनरेगा की महत्वकांशी योजना निश्चय ही एक सामाजिक कल्याण की योजना है। वह विनियमित रूप से रोजगार सृजित करने की योजना नहीं हैं। उपुर्यक्त स्थिति को सुधारने के लिए देश में सभी स्तरों पर बुनियादी सुधार किये जाने की आवश्यकता है जिनकी आशा कांग्रेसनीत् यूपीए सरकार से नहीं की जा सकती।

गरीबी उन्मूलन के बारे में संप्रग सरकार का रवैया हकदारी है न कि सशक्तिकरण का। यद्यपि सशक्तिकरण एक लाभदायक और टिकाऊ रणनीति है तथापि हकदारी लोगों को स्थायी रूप से सरकार पर निर्भर बनाने वाली है।

<u>किसानों की दशा</u>

भारत में कृषि, जिसमें जनसंख्या का 60 प्रतिशत से अधिक लोग लगे हुए हैं, की स्थिति बहुत खराब है। इस खराब स्थिति का एक उदाहरण आत्महत्याओं के ग्राफ से पता चलता है। संप्रग शासन काल के दौरान ''ट्रर्म ऑफ ट्रेड'' हमेशा किसानों के खिलाफ गई है। उन्हें अपने उत्पादों का वास्तविक लाभप्रद मूल्य मिलने के उनके अधिकार से लगातार वंचित रखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने वालों ने हमेशा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की और वे वास्तविकता से अनभिज्ञ रहे। राजग सरकार ने लाभप्रद मूल्यों की गणना का एक व्यवहार्य फार्मूले का सुझाव देने के लिए स्वामीनाथन आयोग नियुक्त किया था। उन्होनें न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50% का अधिक का सुझाव दिया था। संप्रग सरकार लगातार इस फार्मूले को रद्द करती रही और किसानों को वास्तविक लाभप्रद मूल्य प्रदान नहीं किया।

संप्रग सरकार यह दावा करती है कि उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्वि की है। वास्तव में यह इन पुट लागत थी जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तुलना में अधिक बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप, न्यनतम समर्थन मूल्य और इनपुट की लागत में मार्जिन लगातार कम हो गया। अनेक स्थानों पर खरीद केंद्र उस समय काम नहीं करते जब किसान अपना उत्पाद वहां लाते हैं। उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री मजबूरन करनी पड़ती है। यहां तक कि अनेक केंद्रो पर सरकार आवश्यक मात्रा में जूट बैग की सप्ताई नहीं कर पाती जिसके परिणामस्वरूप भारी हानि होती है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग की नवीनतम गणना किसानों के इस प्रकार गिरते मार्जिन की साक्ष्य है। **धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसकी उत्पादन लागत में अंतर 2010–11 में कम होकर 2012–13 में 8% ही रह गया है। गेहूँ के मामले में भी यह अंतर गत् तीन वर्षो के दौरान 33% से कम होकर 13% रह गया है।** वीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों, डीजल और बिजली, पानी की लागत बढ़ गई है। किसान हताश होने पर मजबूर हो गये हैं। **संप्रग सरकार की इस प्रकार की शोषण प्रणाली से किसानों को कम पैसा मिल रहा है जबकि उपभोक्तओं को ऊँचे मूल्य चुकाने पड़ रहे हैं।**

भाजपा मांग करती है कि लाभप्रद मूल्यों की गणना संबंधी स्वामीनाथन समिति के फार्मूले को तुरन्त स्वीकार किया जाये और राजग सरकार द्वारा चालू की गई निश्चित न्यूनतम आय गारंटी योजना को पुनः चालू किया जाये।

भाजपा कृषि के प्रति इस प्रकार की नीति का अनुसरण करने के भावी खतरों के बारे में कांग्रेसनीत संप्रग सरकार को चेतावनी देती है क्योंकि इससे गत् कुछ दशकों के दौरान खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के बारे में भारत की उपलब्धियों को वास्तव में आघात पहुंच सकता है।

संप्रग की उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (NBS) के कारण सभी गैर–सब्सिड़ी वाले उर्वरकों के मूल्यों में वृद्वि हुई है जिसके फलस्वरूप योजना का उद्देश्य ही विफल हो गया है। गैर–यूरिया उर्वरकों के मूल्य भी आसमान छू रहे हैं, जिसके फलस्वरूप यूरिया का अत्याधिक उपयोग हो रहा है। किसानों को उर्वरकों की कम सप्लाई हो रही है और इसके कारण इसकी कालाबाजारी हो रही है। हर वर्ष किसान देश भर में सैकड़ो स्थानों पर इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

सरकार ने पूरी तरह से सिंचाई की उपेक्षा की है जो एक मात्र हमारी वर्षा पर आधारित कृषि को और अधिक टिकाऊ बनाने का मुख्य कारक है। वर्ष 1989 में जब डॉ. मनमोहन सिंह योजना आयोग में थे इसने गत् कुछ वर्षो के दौरान भरपूर फसल को देखते हुए सिंचाई के लिए आवंटन को कम करने का निर्णय लिया था। इस एक विनाशकारी निर्णय के कारण राष्ट्र सिंचाई के मामले में 20 साल पिछड़ गया और इससे कृषि क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई।

<u>सूखा और बेमौसम की बरसात</u>

कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भंयकर सूखे की स्थिति है। देश में 100 से

अधिक जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। फसलें बर्बाद हो गई है। ऋण बढ़ते जा रहे हैं। किसान भारी मुसिबत में है। जल की कमी के कारण अनेक समस्याएं खड़ी हो गई हैं यहां तक की पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो गई है और पानी की कमी के कारण अनेक विद्युत संयंत्र बंद हो गये हैं। पानी और चारे के अभाव में जन पशु शिविर आयोजित करने पड़े। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि मंद पड़ गयी है फिर भी केंद्र सरकार किसानों की सहायता करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने में असफल्त रही है।

जनवरी, फरवरी के महीनों में बेमौसम की बरसात और काफी समय तक सर्दी का मौसम रहने के कारण उत्तरी भारत में खड़ी फसलों को अपूरनीय क्षति पहुंची है। रबी फसल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने की पूरी आशा है और इससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है।

भाजपा माँग करती है कि पीड़ित किसानों के ऋणों को तुरन्त माफ किया जाये और प्रभावित राज्यों को सभी आवश्यक सहायता दी जाये।

<u>भाजपा नीत राजग का राष्ट्रीय विकास में योगदान</u>

भाजपा को कृषि में शानदार कार्य के लिए समग्र विकास और लोगों के हित वाले सुधार करने के लिए अपनी राज्य सरकारों पर गर्व है।

यदि देश की कृषि 3.5% के हिसाब से बढ़ रही है जिसके लिए राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने केन्द्र सरकार को शाबाशी दी है तो यह बात नोट की जानी चाहिए कि भाजपा और राजग शासित राज्यों में औसत कृषि विकास राष्ट्रीय औसत से दो गुना है।

कांग्रेस पार्टी खाद्य सुरक्षा और प्रत्यक्ष नकदी अंतरण योजनाओं के मुद्दे पर अपने राजनीति भविष्य को जोड़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही सफलतापूर्वक खाद्य सुरक्षा योजना संबंधी कानून बनाया है और उसे लागू किया है जिसके अंतगर्त राज्य के 90% लोगों को कवर किया गया है। इस सफल मॉडल की लगातार लगभग सारे विश्व में कवरेज के लिए प्रशंसा की जा रही है। राजग शासित अनेक राज्य पहले से ही छात्रवृत्तियों, पेंशन और अनेक अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से प्रत्यक्ष नकदी अंतरण का अनुपालन का रही है।

भाजपा और राजग शासित राज्यों ने सुराज की अच्छी परम्परा के लाभ तेजी से प्रगति करने का उदाहरण स्थापित किया है। यदि देश में 5% विकास की दर है तो यह केवल राजग शासित राज्यों द्वारा लगातार 10% औसत वार्षिक विकास वृद्वि दर होने के कारण है।

यदि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार अर्थव्यवस्था का सुचारू प्रबंधन नही कर सकती तो उनके द्वारा देश के लिए बेहतर सेवा यह होती कि वे भाजपा और राजग राज्य सरकारों के नये–नये और सफल कार्यक्रमों का अनुसरण करते हुए उन्हें लागू करती।

<u>बजट–2013</u>

28 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। इसमें नीति और कराधान ढांचे में कुछ कास्मेटिक परिवर्तन किए गए हैं। यद्यपि बजट की विषय वस्तु शब्दाडंबर से भरी हुई है, तथापि इसमें अभीष्ट लक्ष्य नजर नहीं आता। इसमें भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं है। .षि की अनदेखी की गई है। यहां तक कि आम आदमी का उल्लेख करने की परम्परा को भी नहीं निभाया गया। इसमें ऐसे किन्हीं कदमों का उल्लेख नहीं है जिनसे निर्यात बढ़े, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो और रूपया मजबूत हो सके। अर्थव्यवस्था को 5 प्रतिशत के विकास दर से नीचे लाकर संप्रग अपने ताजा बजट में 9 प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने प्रारम्भिक रोडमैप तैयार करने में विफल रहा है।

बजट में एक चेतावनी भी है। 96980 करोड़ रूपये की पेट्रोलियम सब्सिडी को कम करके 65000 करोड़ रू. करने का इरादा है। इससे यह पता चलता है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के मूल्य और बढ़ेंगे।

यह बजट कोई नीतिगत वक्तव्य नहीं है। इसमें दिशा संबंधी कोई परिवर्तन नहीं है। यह मात्र हिसाब किताब करने की एक कार्रवाई है जिसमें व्यय को कम किया गया है। उसके बढ़ने की कोई संभावना नहीं बतायी गयी। इससे विकास नहीं बढ़ेगा। गरीब और कमजोर वर्गों के साथ–साथ मध्यम वर्ग भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे।

वर्ष 2012–13 के पुनरीक्षित अनुमानों में राज्यों के पूंजी परिव्यय में 60,000 करोड़ रूपये की भारी कटोती की गई है जो सबसे बड़ा धोखा है। ऐसा बिना किसी बहस के और घोषणा के किया गया है।

वित्तमंत्री ने चालू खाता घाटा (CAD) के वित्त पोषण के लिए अगले दो वर्षों के दौरान 75 बिलियन अमरीकी डॉलर की हमारी आवश्यकता का उल्लेख किया है। उनके अनुसार ऐसा करने के तीन उपाय हैं–एफडीआई, एफआईआई, इसीबी। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार द्वारा आर्थिक सुधार का जो रास्ता अपनाया है वह राष्ट्रीय जरूरत के अनुरूप नहीं है बल्कि यह वैश्विक दबाव से प्रभावित है। प्रत्येक देश को सुधार का अपना स्वयं का रास्ता ढूंढ़ना होता है जो टिकाऊ हो और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इस संबंध में भाजपा का देश को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड है और हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं और दोबारा ऐसा करने के लिए सक्षम हैं।

संक्षेप में अपनी जनविरोधी नीतियों से कांग्रेस ने समाज के गरीब वर्गो और किसानों को भारी हानि पहुंचायी है। मध्यमवर्गीय लोगों की आशाऐ और आंकाक्षांऐ छिन–भिन्न हो गयी हैं। शहरी और ग्रामीण दोनो अर्थव्यवस्थाओं को समान रूप से नुकसान पहुंचा है और नौकरियॉ और विकास बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

अतः भाजपा मांग करती है,

- पेट्रोल, डीजल के प्रशासित मूल्यों में की गयी सभी बढ़ोत्तरी को तुरन्त वापिस लिया जाये और गैस सिलेण्ड़रों की सीमा को समाप्त किया जाये।
- सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को आवश्यक नीति सम्बन्धी सुधार करके कम किया जाये।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाये जो लागत + 50 प्रतिशत के फार्मूले पर आधारित हो।
- किसानों के लिए सुनिश्चित न्यूनतम आय गारन्टी योजना को पुनः चालू किया जाये।
- सूखा और बेमौसम की बरसात से प्रभावित किसानों के ऋण माफ किये जायें।
- उन पात्र किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जाये जो फार्म ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन से वंचित रह गये हैं।
- उरवर्को के मूल्यों को कम करने के लिए तुरन्त कदम उठायें जायें।

यदि यह मांगे पूरी नहीं की जाती तो भाजपा संप्रग सरकार की इन जन–विरोधी और विकास विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन चलाएगी।